ग्रामीण श्रमिकों पर विमुद्रीकरण का प्रभाव

Dr. Dazy Kumari

MA, P.hd

Home Science, Bhupendra Narayan Mandal University, Bihar

Abstract

भारतीय कृषि व्यवस्था जो अत्यधिक असंगठित है मुख्य रूप से नकदी पर आधारित है, जयादातर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने दिन प्रतिदिन के कार्यो के लिए नकदी पर निर्भर रहते हैं। 08 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री के विमुद्रीकरण के निर्णय ने नकद लेन–देन के संबंध में ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया। यह अध्ययन ग्रामीण क्षेत्र में विमुद्रीकरण और कैशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रभाव का मुल्यांकन करने के लिए किया गया है।

विमुद्रीकरण के मुद्दे पर ग्रामीण महिलाओं के साथ बातचीत और इसके प्रभाव के बारे में भी कुछ उल्लेख किया गया है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए विमुद्रीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि विमुद्रीकरण की तैयारी एक तरफा थी और ग्रामीण लोगों पर इसका प्रभाव बहुत भयानक था। कैशलेश अर्थव्यवस्था के विचार को अधिक समग्र दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए। जैसे कि कानून को मजबूत करना नियामकों की क्षमता निर्माण, भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी।

Key Word :– विमुद्रीकरण, दिहाड़ी मजदूर, कैशलेस अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि।

प्रस्तावना :

किसी भी सरकार के द्वारा मुद्रा के किसी भी मूल्य–वर्ग के कानूनी निविदा अधिकारों का वापस लेना विमुद्रीकरण के रूप में जाना जाता है। 08 नवंबर 2016 को प्रधानामंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्र को एक प्रसारण में घोषणा की कि 500 और 1000 रूपए मुद्रा नोटों को अब कानूनी रूप से मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। भारत में प्रचलन में कुल मुद्रा रूपए का मूल्य 16.42 लाख करोड़ ;240 ठपससपवद ै क्वससवतद्ध के मूल्य के नोट भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार थे। सरकार का मानना है कि इस विमुद्रीकरण की आवश्यकता 4 कारणों से हैं।

01) भ्रष्टाचार को कम करना

02) कालाधन को बेकार करना

03) नकली मुद्राओं की समस्या का सामना

04) आतंकवाद की फंडिंग को रोकना

सरकार को इस कदम को गुप्त रखने की आवश्यकता थी, क्योंकि विमुद्रीकरण की घोषणा से पहले कर चोरों का पता नहीं चलता।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि लोगों को बदलाव के साथ तालमेल बैठाने में लगभग 50 दिन लगेंगे। हालांकि उनका यह निर्णय भारत में सबसे ऐतिहासिक कदम है। यह निर्णय

01) मुद्रा स्थिति को नियंत्रित करने

02) बैकों का पुनर्पुजींकरण करने

03) ब्याज दरों को कम करने

04) पुजींप्रवाह के साथ अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाने में मदद कर सकता है।

आलेख का उद्देश्य :

कृषि पर विमुद्रीकरण का बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा। बहुत कम अनुभवजन्य साक्ष खेती और संबंधित गतिविधियों पर विमुद्रीकरण को सही ठहराते हैं। ठपेमद मजण ंस 2017 के प्रारंभिक अध्ययन के द्वारा ये ज्ञात हुआ कि विमुद्रीकरण छोटे और सीमांत किसान एवं श्रमिक, बड़े किसानों के विपरीत ज्यादा प्रभावित हुए। इसका मुख्यकारण उनके द्वारा डिजिटल पेमेंट और चेक का प्रयोग ना करना था।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य :

01) ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं स्वरूपों और भारत में किसानों महिला श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों की स्थिाति को समझना।

02) ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों एंव महिला श्रमिकों पर विमुद्रीकरण के प्रभावों का अध्ययन

03) उनके लिए कैशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रभाव, उपयोगिता पहुँच और उपलब्धता का अध्ययन करना।

क्रिया–विधि

अध्ययन मुख्य रूप से विभिन्न रूपों में प्रकाशित दस्तावेज इंटरनेट अखबारों के लेखों और प्रकाशित रिर्पोटों से विभिन्न रूपों में प्रकाशित प्राथमिक और माध्यमिक ऑकड़ों पर आधारित है।

परिणाम एवं विश्लेषण :

भारत दुनियां का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 2011 कि जनगणना के अनुसार, 130 करोड़ भारतीय जनसंख्या में से लगभग 90 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 40 करोड़ शहरी क्षेत्रों में रहती है। इससे ये साबित होता है कि देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि–गतिविधियों में लगी हुई है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ळक्च् के 17 प्रतिशत के लिए वानिकी, लॉगिंग, फिसिंग जैसे कृषि क्षेत्र का योगदान भारत के समग्र आर्थिक विकास में सबसे अधिक है और रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत भी है।

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव : कृषि क्षेत्र लगभग 49 प्रतिशत लोगों को रोजगार देते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी जटिल है जहां नकदी और सहकारी बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मेरूदंड है। तथ्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लेन–देन के संदर्भ में नकदी हावी है। किसान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ।ज्ड के उपभोग का उपयोग इस क्षेत्र में ना के बराबर है जो कि शहरी क्षेत्र के विपरीत है।

इस प्रकार प्रौद्योगिकी संचालित भुगतान प्रणाली पर निर्भरता ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के पास 1000–500 के नोटों की महत्वपूर्ण संख्या थी, नए करैंसी नोटों की अनुपलब्धता के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

देश भर में नकदी की कमी, ग्रामीण आबादी के बीच बैंकिंग का कम ज्ञान, थोक बाजारों में सब्जियों की मांग में गिरावट के कारण किसानों को झटका लगा। कुछ ने अपनी फसल सस्ती दरों पर बेच दी और कुछ अपनी खरीफ की फसल चावल, सोयाबीन, कपास, गन्ना या रबी फसलों को बेचने के लिए नहीं खरीद सकते थे। किसान बीज खरीदने में कैश की कमी के कारण सक्षम नहीं थे इसलिए नयी गुणवत्ता वाले बीज नहीं खरीद सके। मानसून में अच्छी बारिश होने के बावजूद किसान रबी सिजन 2016 में भारी निवेश करने को तैयार थे क्योंकि 2014 और 2015 में वे सुखे की मार झेल चुके थे। खेती, बुआई पैटर्न, उत्पादकता, बाजार सब प्रभावित हुए।

सरकार के द्वारा उठाए गए कदम :–

1. ऋण की सीमा के अधीन उनके ऋणों को मंजूर किया गया और उनके खातों में जमा किए गए ऋणों के खिलाफ निकासी की सीमा प्रतिसप्ताह 25000 तक निर्धारित की गई।
2. सरकार के किसानों एवं श्रमिकों को किसी भी राज्य या केंन्द्र सरकार के आउटलेट के साथ–साथ किसी भी कृषि अध्ययन संस्थान से बीज खरीदने के लिए पुराने 500रूपय के नोटों का उपयोग की अनुमति दी।
3. ग्रामीण बैंक छंइंतक ने सरकारी बैकों के माध्यम से 3.07 ठपससपवद कवससवत का वितरण करने की घोषणा की थी ताकि किसानों एवं श्रमिकों को सर्दियों की फसल बोने में मदद मिल सकें।
4. 10 राज्यों में 250 स्थानीय थोक बाजारों ने चेक भुगतान स्वीकार करके उपज बेचने के लिए इल्क्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ;म्छ।डद्ध मंच को अपनाया। परंतु सक्रिय बैंक खाता ना होने के कारण यह ज्यादा प्रभावी नहीं रहा।

2. विमुद्रीकरण का सकारात्मक प्रभाव :

1. भरपूर धन के साथ सरकार अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम हो जाती है ताकि सिंचाई के लिए अधिक भूमि आ जाए और एक मौसम में एक फसल के बजाए दो फसलों का उत्पादन कर श्रमिक अपनी आय दोगुना कर सकें।
2. बैंको की ब्याज दरें गिरने लगी जिससे, पुजीगतन लागत कम हो सकी और किसान कृषि यंत्रीकरण के लिए जा सकते हैं।
3. सरकार ब्वसक ैजवतंहम चेन का निर्माण कर सकती है जिससे अपव्यय को कम किया जा सके जो सलाना 80,000 करोड़ है।
4. बिचौलियों और कमीशन एजेंटों पर सख्त रूख से कालेधन को कम किया जाएगा और किसान सीधे उपभोक्ताओं से निपट सकते है और तुरंत भुगतान का श्रेय अपने बैंक खातों में दे सकते हैं।

5. दाल, अनाज, आलू, प्याज आदि आवश्यक वस्तुओं के मालिक नकदी से बाहर निकल जाऐगें और, कीमतों में हेरा–फेरी नहीं कर पाऐगें। जिससे किसान और उपभोगता दोनों लाभान्वित होगें क्योंकि मूल्य–स्थिर रहेगा।
6. उर्वरकों की गुणवत्ता में सुधार होगा और पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी
7. देश के किसानों एवं श्रमिकों के लिए बनाया गया पोर्टल अधिक प्रभावी होगा क्योकि उनके पास स्थानीय और जिला मंडियों के बजाय व्यापक बाजार होगा। वो सीधे अपने बैंक खातों में भुगतान के साथ अपने उत्पादन के लिए अधिक मुल्य प्राप्त करेंगें।
8. खेती अधिक व्यवहार्य हो जाएगी और शहरों से गावों में रिवर्स माइग्रेसन होगा। श्रमिकों के स्मार्टफोन धारण बच्चे अब भविष्य में खेतों पर काम करने से नही कतराऐगें। विमुद्रीकरण हमारे समय की आर्थिक घटनाओं में से एक यादगार अनुभव है। इसका असर हर भारतीय नागरिक को महससू होता है।

वैसे तो दुरगामी लाभ थे परंतु कुछ परेशानी भी हुई जैसे :–

- लंबी–लंबी कतारों में पैसे के लिए खड़े रहना।
- नकदी के ना होने से परिवारों की शादियों और विशेष अवसर भी रद्द करने पड़े जिसका असर उन विक्रेताओं पर हुआ जो उन अवसरों के लिए आपूर्त्ति करते हैं।
- कई स्ट्रीट वेंडरों ने भी अपना कारोबार खत्म कर दिया। इसके अलावा नकद विक्रेताओं, आटोरिक्शा मालिकों टैक्सीचालाकों, दिहाड़ी, मजदूरों छोटे व्यापारियों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ा।

निष्कर्ष :

विमुद्रीकरण भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और वित्तपोषित उग्रवाद से लड़ने के कई चरणों में से एक कदम है। हालांकि विमुद्रीकरण की तैयारी लोप पक्षीय थी और इसका प्रभाव भारतीय जनता पर भयानाक था। यदि 86 प्रतिशत नकदी निकाल ली जाती है तो एक अल्पराशि उपलब्ध होने के साथ सभी बाजारी लेने देने मारे गए हैं। जिन लोगों को निशाना बनाया गया वे सड़कों पर नहीं आए, लेकिन आम जनता अपने काम के स्थानों के साथ–साथ घरों से भी बाहर है।

कालेधन से देश को छुटकारा दिलाने और कर बकायेदारों और कालेधन रखनेवालो को पछाड़ने के इरादे से सरकार ने विमुद्रीकरण का कदम उठाया इस कदम का समांनांतर अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा लेकिन अग्रिम घोषणा करने की अचानक घोषणा और विफलता ने आम जनों में अस्थायी अराजकता और बेचैनी पैदा कर दी।

संदर्भ सुची :

[1] Ministry of Finance. (2017). Demonetisation : To deity or to demonize? Economic survey 2016-17. Retrieved from http://indiabudget, nic.in/es2016-17/echapo3.pdf.

[2] Modi, N, (2016). India takes historic step to fight Corruption Black money & terrorism. Retrieved from http://narendramodi.in/text-of-prime-minister-s-address-to.the-nation-533024.

[3] Asian Development Bank. (2013). India: Rural finance sector restructuring and development. Retrieved from://www.adb.org/sites/default/files/project-document/75076/exec-sum.pdf

[4] http:://www.indianeconomy.net/splclassromm/309/what-are-the-impact-of-demonetization-on-indian-economy/

[5] Alliance for sustainable and Holistic Agriculture. (2016) what do farmers. ovement in India want from budget 2017-18? Retrieved from http://www.Kisanswaraj. inltag/pre-budget-cousultations.

[6] भारत और निवेश पर विमुद्रीकरण का प्रभाव http://marketreakind/2016/11/can-demonetization-impact-indianeconomy[1]

[7] http://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/12/12/one-month-in-whats-the-effect-of-indias-demonetization-fiasco/#26cle8e62eba